माननीय न्यायमूर्ति एमएम कुमार के समक्ष

जगबीर सिंह — ***याचिकाकर्ता***

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य — ***उत्तरदाता***

सीडब्ल्यूपी नं. 1988 का 6478

9 अप्रैल, 2003

"भारतीय संविधान, 1950—अनुच्छेद 225—पंजाब पुलिस नियम, 1934—नियम 16.2 और 16.21—अनुशासनात्मक बल के सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला—विभाग ने उसे निलंबित किया—नियम 16.2 द्वारा प्रवृत्ति की सबसे गंभीर दोष के लिए निष्कासन का प्रतिद्वंद्वी दंड दिया जा सकता है—क्या निलंबन अवधि के दौरान अनुमत अवकाश के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित होना एक गंभीर दोष का हिस्सा है—सही माना गया—प्राप्तकर्ता भी अपने पेंशन लाभ का हकदार नहीं है क्योंकि उन्होंने योग्य सेवा नहीं दी—याचिका खारिज की गई और सेवा से निकालने के आदेश को स्थायी रूप से स्वीकार किया गया।

प्रतिष्ठापित किया गया कि नियम 16.2 का अध्ययन केवल यह दिखाता है कि निष्कासन का दंड केवल सबसे गंभीर दोष के लिए प्रदान किया जा सकता है, जो अवसुधारण और पुलिस सेवा के लिए पूरी तरह अयोग्यता का सबूत प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध किया गया है कि निष्कासन के आदेश पास करते समय, प्राधिकृत प्राधिकरण को दोषी अधिकारी की सेवा की अवधि और उसके पेंशन के दावे को विचार में लेना चाहिए। नियम 16.21 यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि निलंबन के दौरान पुलिस अधिकारी को उसी जिम्मेदारियों, अनुशासन और दण्डों के तथा उसी प्राधिकरणों के तहत काम करना चाहिए, जैसे कि उसे निलंबित नहीं किया गया हो।" लाइनों पर स्थानांतरण के बाद, उसे पुलिस सुपरिंटेंडेंट द्वारा निर्दिष्ट किए गए सभी कर्त्तव्यों के लिए रोल कॉल में भाग लेने और उन्हें निभाने की आवश्यकता है।

(पैरा 8)

आगे निष्कर्षित किया गया कि निलंबन के दौरान या अन्यथा कर्तव्य से अनुपस्थित होने का कारण नियम 16.21 की निर्दिष्ट भाषा के कारण एक विभिन्न स्तर पर नहीं खड़े होगा। और अन्यथा, कर्त्तव्य से अनुपस्थित होने का एकल कृत्य को गंभीर दोष के रूप में देखा जा सकता है। दोहरी अनुपस्थिति, विशेष रूप से एक दिन एक दंड बल के सदस् के लिए, असुधारणीयता का सबसे गंभीर दोष साबित कर सकती है।

(पैरा 9)

और यह भी निष्कर्षित किया गया कि यह तर्क कि नियम 16.2 के आधार पर प्रापत्रकर्ता की सेवा की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उसकी विस्तृत विचार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह तथ्य के कारण है कि प्रापत्रकर्ता को कोई पेंशन संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं होगें क्योंकि उन्होंने 1 जनवरी 1972 को सेवा में शामिल हुए थे और उन्होंने 17 मई 1979 को निलंबित किया गया था। उनकी विभाग में कुल सेवा की अवधि केवल सात साल से थोड़ी ज्यादा है, जो उपभोक्त वृद्धि को रुकवाने जैसी कम दंड देने के रूप में उसे अल्प पूरी आधार के रूप में देने के लिए विभाग को किसी संविदानिक दिशा में नहीं लेने की आवश्यकता है।

(पैरा 12)

आशीष कपूर, प्राध्यापक, प्रापत्रकर्ता के लिए।

एन. के. जोशी, सरकारी वकील, हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।

<u>न्यायालय का निर्णय</u>

एम.एम. कुमार, न्यायमूर्ति

(1) इस याचिका को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को अदूरी कार्यवाही के कारण 17 जून, 1980 को पुलिस महासंचालक, सोनीपत द्वारा किये गए नामांकन को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। पुलिस महासंचालक द्वारा पास किए गए आदेश को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, गुडगाँव रेंज, गुडगाँव और पुलिस महासंचालक, हरियाणा द्वारा मंजूरी दी गई है,— 6 सितंबर, 1981 को और 20 मार्च, 1986 को किए गए आपत्ति और संविधानात्मक पुनरावलोकन के आदेश के तहत। उपर्युक्त आदेशों, यानी अनेक्षर P-2 और P-3, इस याचिका के विरुद्ध भी बने हुए हैं और उन्होंने इस याचिका के विषय में चुनौती का मुद्दा बना दिया है।इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया यादगार, यानी अनेक्षर P-7, को हरियाणा के उच्चायुक्त ने भी खारिज कर दिया है।

(2) मामले के संक्षेपित तथ्य हैं कि प्रापत्रकर्ता 1 जनवरी, 1972 को सोनीपत जिले में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए। 15 मई, 1979 को उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 और 109 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए वहां पुलिस स्टेशन गोहाना में एफआईआर नंबर 88 दर्ज की गई। उसे 17 मई, 1979 को निलंबित किया गया और उसका मुख्यालय पुलिस लाइंस, सोनीपत में निर्धारित किया गया। कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के आलोचनाओं के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 4 ने उस पर आरोप प्रतियां देने के लिए चार्ज-शीट दी कि उसने मंजूर किए गए अवकाश के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित रहे। एक नियमित विभागीय जांच हुई और जांच अधिकारी ने खुदरा निष्कर्ष दिया कि प्रापत्रकर्ता द्वारा कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के आरोप के खिलाफ उन्हें दोषी पाया गया कि 5 अक्टूबर, 1979 से 6 अक्टूबर, 1979, 8 जनवरी, 1980 और 26 फरवरी, 1980 के दौरान कर्तव्य से अनुपस्थित रहे। फिर भी, उसे उन अन्य दो कालों के लिए कोई दण्ड नहीं मिला, जिनके बारे में आरोप लगाया गया था, अर्थात् 17 अक्टूबर, 1979 और 20/21 अक्टूबर, 1979, क्योंकि पहले ही दंड दिया गया था। पुलिस महासंचालक,— आदेश दिनांक 17

जून, 1980 के तहत, प्रापत्रकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। उपर्युक्त आदेश का तात्पर्य निम्नलिखित रूप से है:—

> उपर्युक्त चर्चा के आधार पर, मैं दोषी कांस्टेबल जगबीर सिंह, नंबर 467 को, उसके खिलाफ प्राप्त तीन अनुपस्थिति काल के आरोपों के लिए दोषी मानता हूँ, जैसे कि 5 और 6 अक्टूबर, 1979, 8 जनवरी, 1980 और 26 फरवरी, 1980 के दिनों के लिए। जब बात दो अनुपस्थिति कालों, जगबीर सिंह, व. हरियाणा और अन्य 581 (एम.एम. कुमार, न्यायाधीश) अर्थात् 17 अक्टूबर, 1979, 20/21 अक्टूबर, 1979 की है, तो मैं उन दोषी कांस्टेबल को इन आरोपों से निर्दोष करता हूँ क्योंकि उन्हें पहले ही इन अनुपस्थितियों के लिए पदनिरीक्षण के दंड दिए गए थे।
>
> जितना कि उनकी ऊपर संदर्भित तीन अनुपस्थिति के संबंध में दण्ड का मतलब है, मेरा विचार है कि पुलिस विभाग एक ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कभी भी आ सकता है, बल्कि यह एक अनुशासित बल है और यदि इस प्रकार के पुलिस अधिकारी, जिनके पास सेवा की दीर्घ अनुभव है, बिना किसी अवकाश या अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अनुमति प्राप्त किए बिना कर्तव्य से अनुपस्थित रहने का बार-बार अवगत किए बिना रहें, तो पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखना संभव नहीं है। 4.1/2 महीने से बार-बार गैरमौखिक रूप से गायब रहना और बार-बार DSP/Hqrs. के चेतावनियों के बावजूद बिना किसी योग्य कारण और बिना अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए, यह निश्चित रूप से दुर्व्यवहार की एक गंभीर क्रिया है और इस तरह के असुधार्य और अअनुशासित पुलिस अधिकारी को जिसे अपना कर्तव्य मानने का कोई दुयुति नहीं है, पुलिस बल में बने रहने के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त है, ऐसा होने के बावजूद कोई दण्ड जो केवल पुलिस बल से निष्कासन का दण्ड हो, इस मामले में न्याय के आदेशों को पूरा नहीं करेगा।"मैं, इसलिए दोषी कांस्टेबल जगबीर सिंह को तुरंत प्रभाव से पुलिस बल से निष्कासित करता हूँ।"

(3) प्रस्तावना का आपील, संशोधन और याचिका द प्रस्तावन को अस्वीकृत किया गया है, जैसा कि अनुषंग P-2, P-3 और P-7 के आदेशों में दर्शाया गया है।

(4) उत्तरदायी 1 से 3 द्वारा दाखिल की गई लिखित बयान में कहा गया है कि पुलिस बल एक अनुशासन बल है और अनुशासन को अनुकूल नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि पंजाब पुलिस नियमों की धारा 16.21 के प्रावधानों पर भरोसा किया गया है, जो हरियाणा को लागू होने वाले हैं (संक्षेप में, 'नियम') जिसमें यह उल्लिखित है कि सस्पेंड किए गए पुलिस अधिकारी को यह जिम्मेदारी, अनुशासन और दण्डों के प्रति वही सहमति रखते हैं, जैसे कि उन्होंने सस्पेंड नहीं किया गया हो। यह आगे कहता है कि एक बार नियम 16.21 के उप-नियम (2) के अंतर्गत लाइन्स में पोस्ट किया जाता है, तो अधिकारी को रोल कॉल में भाग लेने और पुलिस के सुपरिंटेंडेंट द्वारा निर्दिष्ट की गई कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है।

(5) नियम 16.2 के द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले गंभीर दुराचार के रूप में कोई मंजूर अवकाश के बिना निलंबन के कर्तव्य से अभाव होने पर श्री आशीष कपूर, प्राध्यापक, मुखर्ग में यह जवाब दिया कि नियम 16.2 के अनुसार अत्यंत दुराचार परिभाषित नहीं होगा। अपनी स्थापना के समर्थन में, प्राध्यापक ने इस महकमे के एक विभागीय बेंच न्यायाधिकरण के मामले में **रामेश चंद्र चुग, सहायक अभियंता (नागरिक) बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड 1986 (3) S.L.R. 1** के मामले का साहारा दिया है। उनके अनुसार, अभाव का कृत्य किसी भी स्पष्टिकरण के कौनसे भी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं पड़ता है जो अनुशासन की प्रक्रिया में अत्यधिक दुराचार की परिभाषा है। प्राध्यापक ने दर्शाया है कि उपयुक्त नियम 16.2 के द्वारा प्राध्यापक की सेवा की अवधि का मूल्यांकन करने में असफल रहे हैं।

(6) एन.के. जोशी, ज्ञानवान राज्य प्राधिकृत, यह दावा कर रहे हैं कि निलंबन के दौरान कर्तव्य से गायब रहना एक गंभीर अनैतिक कृत्य माना जाता है और इसे मान लिया नहीं जा सकता कि एक निलंबित पुलिस अधिकारी को स्वीकृत अवकाश के बिना गैरकानूनी रूप से गायब रहने का अधिकार है।उनका दावा है कि एक निलंबित पुलिस अधिकारी को स्वीकृत अवकाश के बिना गायब रहने देने से नियम 16.21 का उल्लंघन होगा, जिसके अनुसार ऐसे एक पुलिस अधिकारी को जब लाइनों में भेजा जाता है, वह सभी रोल कॉल में शामिल होने के लिए कर्तव्यबद्ध है। अपने तर्क को समर्थन देने के लिए, श्री जोशी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का संदर्भ दिया है, **जिसमें संघ और अन्य बनाम नरेंद्र सिंह AIR 2002 S.C. 2102** मामला है।

(7) पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद मेरा मानना है कि यह याचिका खारिज किये जाने योग्य है। नियमों के नियम 16.2 और 16.21 का संदर्भ लिया जा सकता है जो इस प्रकार हैं:-

"**16.2. बर्खास्तगी** - बर्खास्तगी केवल कदाचार के सबसे गंभीर कृत्यों के लिए या अशुद्धि साबित करने वाले निरंतर कदाचार के संचयी प्रभाव के रूप में दी जाएगी।

पुलिस सेवा के लिए पूरी तरह से अस्वास्थ्यकर। ऐसा अधिनिर्णय देने में अपराधी की सेवा की अवधि और पेंशन के लिए उसके दावे का उल्लेख किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले पुलिस अधिकारी के संबंध में कदाचार के सबसे गंभीर कृत्यों के रूप में माना जाएगा।__

1. जासूसी या तस्करी गतिविधियों में लिप्त होना;
2. परिवहन या संचार के साधनों को बाधित करना;
3. सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना;
4. साथी पुलिसकर्मियों के बीच अनुशासनहीनता पैदा करना;
5. धर्म, नस्ल, जाति, एकता या भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देना;
6. हड़ताल पर जाना या सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाना या सामूहिक बहिष्कार का सहारा लेना;
7. सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाना; और
8. दंगे और इसी तरह के दंगे हो रहे हैं।

"**16.21. निलम्बित अधिकारियों की स्थिति और व्यवहार-**(i) कोई पुलिस अधिकारी पद से निलंबित किए जाने के कारण पुलिस अधिकारी नहीं रहेगा।

इस तरह के निलंबन की अवधि के दौरान एक पुलिस अधिकारी के रूप में उसे निहित शक्तियां, कार्य और विशेषाधिकार स्थगित रहेंगे, लेकिन वह समान जिम्मेदारियों, अनुशासन और दंड और उन्हीं अधिकारियों के अधीन रहेगा, जैसे कि उसे निलंबित नहीं किया गया था।

1. निलंबित पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, अगर वह पहले से ही वहां तैनात नहीं है। वह सभी रोल कॉल में भाग लेगा और उसे ऐसे कर्तव्यों का पालन करने और अधीक्षक के रूप में ऐसी परेड में भाग लेने की आवश्यकता होगी, जैसा कि अधीक्षक निर्देशित करेगा:

बशर्ते कि वह किसी पुलिस अधिकारी की शक्तियों या कृत्यों का प्रयोग करने वाले गार्ड ड्यूटी या किसी अन्य कर्तव्य का पालन नहीं करेगा; जिम्मेदारी के प्रयोग से जुड़े किसी भी कर्तव्य पर नहीं रखा जाएगा और गोला-बारूद के साथ जारी नहीं किया जाएगा। निलंबित पुलिस अधिकारी आमतौर पर ड्यूटी से बाहर होने पर लाइनों तक सीमित रहेगा, लेकिन उसे अपने बचाव की तैयारी के लिए उचित सुविधाओं की अनुमति दी जाएगी। इस नियम के तहत लाइनों में स्थानांतरित होने पर निचले अधीनस्थ अपनी बेल्ट और ऊपरी अधीनस्थों को अपनी रिवॉल्वर, बेल्ट और तलवारें लाइन अधिकारी के पास जमा करेंगे।

xx xx xx xx

(8) नियम 6.2 का अध्ययन दिखाता है कि बर्खास्ती की सजा केवल सबसे गंभीर अनैतिक कृत्य के लिए दी जा सकती है, जो दुर्यवहता और पुलिस सेवा के लिए पूरी तरह अयोग्यता को साबित करते हैं। यह भी व्यवस्थित किया गया है कि बर्खास्ती के आदेश पास करते समय प्राधिकृत प्राधिकरण को दोषी अधिकारी की सेवा की अवधि और पेंशन की मांग को मध्यस्थता में लेनी चाहिए। नियम 16.21 स्पष्ट रूप से इसे दर्ज करता है कि निलंबन के दौरान एक पुलिस अधिकारी को वही जिम्मेदारियों, अनुशासन और दंडों के तहत और उनी समर्थनित प्राधिकरणों के समक्ष रहना चाहिए, जैसे कि उसे निलंबित नहीं किया गया हो। लाइनों में स्थानांतरित होने पर, उसे रोल कॉल्स में भाग लेने और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा निर्दिष्ट सभी कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता होती है। नियम 16.21 का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के **पंजाब राज्य और अन्य बनाम धरम सिंह (1997) 2**

S.C.C. 550 के मामले में आया था, जिसमें उनके उच्चाधिकारी निम्नलिखित रूप से टिप्पणी किया:—

> "इस पैसेज से स्पष्ट होता है कि निलंबन के दौरान भी पुलिस अधिकारी को रोल-कॉल पर जाने और प्राधिकरणों के लिए उपलब्ध रहने की आवश्यकता होती है। निलंबन नियम के तहत निर्धारित सहायता भत्ते का भुगतान एक पहलू है, और उसका कर्तव्य उपस्थित रहने का होता है। सहायता भत्ते का ना मिलना एक दोषी अधिकारी को कार्य से अनुपस्थित होने का अधिकार नहीं देता। उसका कर्तव्य है कि वह सहायता भत्ता का दावा करे, कार्यालय जाए और सहायता भत्ता जमा करे, और यदि यह नहीं भुगतान किया जाता है, तो उच्च प्राधिकरणों के पास आवश्यक प्रस्तावना दे और यदि शिकायत नहीं दूर होती है, तो उपयुक्त संवाद के लिए भुगतान की मांग की जा सकती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि स्पष्ट नियम के सामने, दोषी अधिकारी कार्य से अनुपस्थित हो सकता है। इस परिस्थितियों के बावजूद, दंड अधिकारिता का निष्कर्ष जो कि उन्होंने इच्छाशक्ति से कार्य से गायब रहने का निष्कर्ष दिया है, वह सही है।

(9) "सुप्रीम कोर्ट के **धरम सिंह के मामले** में दिए गए उक्त टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि सस्पेंशन के दौरान या अन्य किसी समय अधिकारी की अनुपस्थिति को नियम 16.21 की विशेष भाषा के कारण एक अलग मंच पर नहीं रखा जा सकता है। और फिर भी, यह अच्छा तरीके से स्थापित है कि कार्य से अनुपस्थिति का एक एकल कृत्य गंभीर दोष के कृत्य के रूप में देखा जा सकता है। बार-बार की अनुपस्थिति, विशेष रूप से एक दंडनीय बल के सदस्य के लिए 'सुधारने का असंभाव' का सबसे गंभीर कृत्य साबित हो सकती है। वर्तमान मामले में, प्राधिकरण ने 17 अक्टूबर 1979 और 20/21 अक्टूबर 1979 को अनुपस्थित रहने पर उन्हें ड्रिल की सजा दी थी। उनके बिना किसी अधिकारिक अवकाश के 8 जनवरी 1980 और 26 फरवरी 1980 को भी वे अनुपस्थित रहे। नियम 16.2 का मामला **सुप्रीम कोर्ट के पंजाब राज्य और अन्य बनाम सुखविंदर सिंह 1999 S.C.C. (L&S) 1234 के** मामले में उनके

उच्चाधिकारियों द्वारा विचारण किया गया था और बार-बार की अनुपस्थिति के बारे में निम्नलिखित रूप से कहा गया है:"

> " उच्च न्यायालय का यह कहना सही था कि प्रतिवादी एक अनुशासित बल का सदस्य था और ड्यूटी से अनुपस्थित रहना इस तरह के बल के सदस्य के लिए अनुचित था। यह उस प्रकाश में था कि उच्च न्यायालय को प्रतिवादी की ड्यूटी से अनुपस्थिति के बार-बार किए गए कृत्यों को देखना चाहिए था। यह तथ्य कि प्रतिवादी अनुसूचित जातियों का सदस्य है, न तो यहां है और न ही इस बात पर विचार करने के उद्देश्य से कि वह कदाचार और अनुशासन के उल्लंघन का दोषी है या नहीं, न ही यह तथ्य कि वह अपनी मां को अपना वेतन देने गया था और उसकी बीमारी के कारण हिरासत में लिया गया था। यह आवश्यक है कि पुलिस बलों के सदस्यों को उन कर्तव्यों में भाग लेना चाहिए जो उन्हें आवंटित किए गए हैं और स्वयं अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। यह एक सर्वोपरि सार्वजनिक हित है जिसे निजी विचारों पर भारी होना चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कई कृत्यों को सौम्य रूप से देखने में स्पष्ट त्रुटि की।
>
> बर्खास्तगी के आदेश में 'कदाचार के सबसे गंभीर कृत्य' के 'मंत्र' का इस्तेमाल नहीं किया गया है. उस निष्कर्ष का सार उस क्रम में पाया जाना है। जब कोई पुलिसकर्मी बार-बार ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, तो यह उचित रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उसके निरंतर दुर्व्यवहार में अशुद्धि है।”

(10) इसके अलावा, सजा की मात्रा में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता कि जांच अधिकारी द्वारा कुछ चूक की गई है। यह उल्लेख करना उचित है कि जांच अधिकारी की ओर से निष्कर्षों या प्रक्रियात्मक चूक की वैधता को चुनौती देने के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है। **नारायण सिंह के मामले (सुप्रा**) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस विचार का समर्थन होता है।

(11) याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील का तर्क कि निलंबन के दौरान अनुपस्थिति का सबसे गंभीर कार्य नहीं होगा इसलिए, कदाचार को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **धरम सिंह की** मामला (सुप्रा)के मद्देनजर इसे खारिज कर दिया जा सकता है।

(12) विद्वान वकील द्वारा उठाए गए अन्य तर्क कि नियमों के नियम 16.2 के आधार पर याचिकाकर्ता की सेवा की अवधि को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था, इस तथ्य के कारण किसी भी विस्तृत विचार की आवश्यकता नहीं होगी कि याचिकाकर्ता को कोई पेंशन अधिकार प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वह 1 जनवरी को सेवा में शामिल हो गया था। 1972 में उन्हें 17 मई, 1979 को निलंबित कर दिया गया। विभाग में उनकी सेवा की कुल अवधि केवल सात वर्ष से अधिक है, जो विभाग के लिए उन्हें कम सजा देकर उदार दृष्टिकोण अपनाने का शायद ही कोई आधार होगा, जैसे संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि को रोकना आदि। धरम सिंह के मामले (सुप्रा) में बर्खास्तगी के आदेश को समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश में बदल दिया गया था क्योंकि अधिकारी ने लंबे समय तक सेवा दी है और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। इस दृष्टिकोण को तत्काल मामले में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता ने ऐसी योग्यता सेवा प्रदान नहीं की है जो उसके लिए पेंशन अर्जित करने के लिए पर्याप्त हो। इसलिए, विद्वान वकील द्वारा की गई दूसरी दलील में कोई दम नहीं है और रिट याचिका खारिज की जा सकती है।

(13) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

<u>अस्वीकरण :</u>

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee JudicialOfficer)

अंबाला,हरियाणा